

केंद्रीय विद्यालय संगठन

बनाम

अरुणकुमार माधवराव सिन्ध्ये और अन्य

31 अक्टूबर, 2006

(जी. पी. माथुर और ए. के. माथुर, जे. जे.)

सेवा कानून

सेवाओं की समाप्ति-शारीरिक शिक्षा शिक्षक अस्थायी पोस्ट पर-छात्रों द्वारा शिकायत कि वह उन्हें शारीरिक दंड दे रहा था-स्कूल के प्राचार्य द्वारा अपने क्षेत्रीय कार्यालय को अग्रेषित किया गया जिसके द्वारा मूल बयानों के साथ एक रिपोर्ट मांगी गई थी-उस उद्देश्य के लिए जांच की गई जिसमें छात्रों के बयान दर्ज किए गए और उक्त शिक्षक से स्पष्टीकरण मांगा गया-पूछताछ अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की, लेकिन क्षेत्रीय कार्यालय ने सेवाओं को समाप्त करने का आदेश दिया-उच्च न्यायालय द्वारा समाप्ति को अवैध-शुद्धता- माना गया कि जांच केवल एक प्रारंभिक या तथ्य खोजने वाली जांच थी, न कि एक औपचारिक पूर्ण विभागीय जांच जहां निर्धारित प्रक्रिया व नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का पालन नहीं किया गया है-आरोपों का अनुच्छेद नहीं दिया गया ना ही विद्यार्थियों को शपथ पर परीक्षित कराया गया-बिना एक महीने के

नोटिस के सेवाओं को समाप्त करने के लिए प्राधिकरण की नियुक्ति किसी भी कारण को निर्दिष्ट करना-यह अधिक था क्योंकि समाप्ति आदेश हानिरहित था और इसमें कोई कलंक नहीं था।

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 311-अनुच्छेद के अंतर्गत पद की प्रयोज्यता केंद्रीय विद्यालय संगठन में शिक्षक का पद एक सिविल पद नहीं है और उसके प्रावधान सेवा से उनकी समाप्ति के मामले में लागू नहीं होते हैं।

उत्तरदाता को शारीरिक शिक्षा के एक अस्थायी पद पर नियुक्त किया गया था। एक छात्र के पिता ने शिकायत की कि डॉक्टर की सलाह और कक्षा शिक्षक के लिखित नोट के बावजूद, उक्त टीचर ने उनके बेटे को व्यायाम करने के लिए मजबूर किया और ऐसा करने में असमर्थ होने पर उसे पीटा गया। यह आगे आरोप लगाया गया कि यह एकमात्र अवसर नहीं था जब प्रतिवादी द्वारा छात्रों को शारीरिक दंड दिया गया था। अपीलार्थी विद्यालय के प्राचार्य द्वारा उक्त शिकायत को अपने क्षेत्रीय कार्यालय में अग्रेषित किया गया जहां से उनसे मूल दस्तावेजात के साथ एक रिपोर्ट मांगी गई। उक्त प्रयोजन के लिए एक विद्यार्थियों के जांच अधिकारी ने तब प्रतिवादी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश करते हुए अपनी राय प्रस्तुत की। लेकिन अपीलार्थी के क्षेत्रीय कार्यालय ने प्रत्यर्थी की सेवाओं को समाप्त कर दिया। प्रत्यर्थी ने एक घोषणा के लिए मुकदमा

दायर किया कि उनकी सेवाओं की समाप्ति इस आधार पर अवैध थी कि जांच में उनके खिलाफ निष्कर्ष दर्ज किया गया था और उनकी पीठ के पीछे किया गया थाय यह सेवाओं की समाप्ति का एक साधारण आदेश नहीं था, बल्कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए दंड के रूप में पारित किया गया था। ट्रायल कोर्ट ने मुकदमे को खारिज कर दिया और निचली अपीलीय अदालत में पहली अपील भी खारिज कर दी गई। हालाँकि, प्रत्यर्थी द्वारा दायर दूसरी अपील को उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया और मुकदमे का फैसला सुनाया गया। इसलिए वर्तमान अपील।

अपीलार्थी ने तर्क दिया कि प्रत्यर्थी के खिलाफ की गई जाँच एक अनुशासनात्मक जाँच नहीं थी, बल्कि केवल प्रारंभिक या तथ्य खोजने वाली जाँच की प्रकृति में थी।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया

1.1 प्रत्यर्थी के खिलाफ की गई जांच की प्रकृति थी प्रत्यर्थी के खिलाफ अनुशासनात्मक जांच की गई और उसे किसी भी आरोप के साथ पेश नहीं किया गया या उस संबंध में कोई और कदम नहीं उठाया गया। इसके बजाय उन्होंने नियुक्ति आदेश के नियमों और शर्तों के तहत शक्ति का प्रयोग करने का विकल्प चुना। समाप्ति आदेश पूरी तरह से हानिरहित है और प्रतिवादी पर कोई कलंक नहीं लगाता है और न ही यह उसे किसी भी बुरे परिणाम के साथ देखता है।

1.2 प्रधानाचार्य प्रतिवादी पी. टी. मास्टर से संबंधित घटना और प्रतिवादी द्वारा अन्य छात्रों को दी गई शारीरिक सजा के चश्मदीद गवाह नहीं थे। इसलिए, पूर्ण तथ्यों का पता लगाने के लिए संबंधित छात्रों से पूछताछ करना आवश्यक था। यदि इस जांच के दौरान प्रतिवादी को भाग लेने की अनुमति दी गई थी और केंद्रीय विद्यालय संगठन छात्रों से कुछ सवाल किए गए थे, इसका मतलब यह नहीं होगा कि इस तरह से की गई जांच ने एक औपचारिक विभागीय जांच का रूप ले लिया। प्रत्यर्थी पर कोई आरोप नहीं लगाया गया था और न ही छात्रों को शपथ लेने के लिए कहा गया था। उच्च न्यायालय ने अभिलेख पर साक्ष्य को गलत पढ़ा है यह देखते हुए कि प्रत्यर्थी पर आरोप के लेख लगाए गए थे। जाँच का सीमित उद्देश्य प्रासंगिक तथ्यों का पता लगाना था ताकि आयुक्त, केंद्रीय विद्यालय संगठन, बॉम्बे क्षेत्र ने प्रत्यर्थी की सेवाओं को उनके नियुक्ति आदेश में उल्लिखित नियमों और शर्तों के अनुसार समाप्त कर दिया, जो स्पष्ट रूप से उन्हें शक्ति प्रदान करते थे।

कोई कारण बताए बिना एक महीने के नोटिस द्वारा प्रत्यर्थी की सेवाओं को समाप्त करने के लिए नियुक्ति प्राधिकरण। इसलिए, प्रतिवादी की सेवाओं को सजा के रूप में समाप्त नहीं किया गया था।

महाराष्ट्र राज्य बनाम वीरप्पा आर. साबोजी, आकाशवाणी (1980)
एससी 42, राज्य उत्तर प्रदेश और अन्न. बनाम कौशल किशोर शुक्ला,

(1991) 1 एस. सी. सी. 691, एस. पी. वासुदेव बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, आकाशवाणी (1975) एससी 2292, रवींद्र कुमार मिश्रा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम लिमिटेड और अन्य आकाशवाणी (1987) एससी 2408, पवनेंद्र नारायण वर्मा बनाम संजय गांधी पीजीआई ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड अन्य (2002) 1 एस. सी. सी. 52 और पंजाब राज्य बनाम सुखविंदर सिंह (2005) 5 एस. सी. सी. 569, ने भरोसा किया समशेर सिंह बनाम पंजाब और अन्न राज्य (1974) 2 एस. सी. सी. 831, बिशन लाल गुप्ता बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, (1978) 1 एस. सी. सी. 202, अनूप जैसवाल बनाम भारत सरकार और अन्य, (1984) 2 एस. सी. सी. 369 और दीप्ति प्रकाश बनर्जी बनाम सत्येंद्र नाथ बोस राष्ट्रीय बुनियादी विज्ञान केंद्र, कलकत्ता और अन्य, (1999) 3 एससीसी 60 विशिष्ट

2. प्रतिवादी को केंद्रीय विद्यालय में पी. टी. शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था संगठन और इस तरह वह संविधान के अनुच्छेद 311 के अर्थ के भीतर एक नागरिक पद नहीं रखता है और उक्त प्रावधान उस पर लागू नहीं होता है।

सिविल अपील न्यायनिर्णय: सिविल अपील सं 5452-5453/2004

बॉम्बे उच्च न्यायालय के दूसरी अपील संख्या 463/1998 और सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट (2006) एस. पी. 7 एस सी आर दूसरी अपील

संख्या 463-1998 में याचिका संख्या 6-2003 के निर्णयों और आदेशों दिनांक 5.3.2002 और 3.11.2003 की समीक्षा करें।

अपीलार्थी के लिए एस. राजप्पा।

उत्तरदाता के लिए टी. राजा।

न्यायालय का निर्णय जी. पी. माथुर, जे. द्वारा दिया गया था।

1. इन अपीलों को विशेष अनुमति द्वारा बॉम्बे उच्च न्यायालय के दिनांकित 5.3.2002 के फैसले और डिक्री के खिलाफ प्राथमिकता दी गई है। जिसे प्रत्यर्थी अरुणकुमार माधवराव सिंधधाये द्वारा दायर दूसरी अपील को स्वीकार कर लिया गया और उनके द्वारा दायर मुकदमे को दिनांक 1 की सेवाओं की समाप्ति के आदेश को दरकिनार करते हुए और पूर्ण वेतन के साथ उनकी बहाली का निर्देश देते हुए फैसला सुनाया गया। अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक समीक्षा याचिका को प्राथमिकता दी जिसे 3.11.2003 पर खारिज कर दिया गया था और उक्त आदेश को भी चुनौती दी गई है।

2. प्रतिवादी अरुणकुमार माधवराव सिंधधाये को केंद्रीय विद्यालय में शारीरिक शिक्षा शिक्षक के एक अस्थायी पद पर नियुक्त किया गया था। 25.6.1974 पर संगठन। नियुक्ति आदेश में उल्लिखित नियुक्ति की शर्तों के अनुसार दिनांक 21.3.1975 के आदेश के माध्यम से उनकी सेवाओं को

समाप्त कर दिया गया था। उन्होंने एक घोषणा के लिए एक मुकदमा दायर किया कि उनकी सेवाओं की समाप्ति का आदेश दिनांक 21.3.1975 अवैध, निष्क्रिय और बाध्यकारी नहीं था। उसे प्रत्यर्थी द्वारा दायर मुकदमे में मुख्य याचिका यह थी कि उसकी सेवाओं को एक जांच के रूप में सजा के रूप में समाप्त कर दिया गया था।

उसकी पीठ के पीछे रखा गया था जिसमें कुछ गवाहों से पूछताछ की गई थी और जांच पूरी होने के बाद, जिसमें उसे अपना बचाव करने का कोई मौका नहीं दिया गया था, उसके खिलाफ एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी और उक्त रिपोर्ट के आधार पर उसकी सेवाओं को समाप्त कर दिया गया था। मुकदमे का बचाव किया गया था

अपीलार्थी कई आधारों पर और मुख्य आधार यह है कि याचिकाकर्ता की सेवाओं को सजा के रूप में नहीं, बल्कि नियुक्ति आदेश के संदर्भ में समाप्त किया गया था। विद्वान सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ प्रभाग) पुणे ने दिनांक 2 के फैसले और डिक्री के माध्यम से मुकदमे को खारिज कर दिया और उक्त डिक्री के खिलाफ प्रतिवादी द्वारा दायर अपील को भी 7 वें अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, पुणे द्वारा दिनांक 1 के फैसले और डिक्री द्वारा खारिज कर दिया गया। हालाँकि, प्रत्यर्थी द्वारा दायर दूसरी अपील को उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया था और मुकदमे का फैसला किया गया था जैसा कि पहले उल्लेख किया गया था।

3. पक्षकारान के विद्वान वकील के द्वारा दिये गए निवेदन स्वीकार करने से पहले, मामले के आवश्यक तथ्यों व उच्च न्यायालय द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष उल्लेखित करना सुविधाजनक होगा।

4. केंद्रीय विद्यालय संगठन, बॉम्बे क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रतिवादी के पक्ष में जारी नियुक्ति आदेश का प्रासंगिक भाग निम्नानुसार है:

सं.एफ.6-7/74/7 केवीएस (बीआर)

तारीख: 25 जून, 1974

स्मारक

विषय: शारीरिक शिक्षा हेतु शिक्षक के पद पर नियुक्ति का प्रस्ताव।

उपरोक्त पद के लिए उसके आवेदन के संदर्भ में, श्री अरुणकुमार माधवराव सिद्धाये को हस्ताक्षरित प्रस्ताव शारीरिक शिक्षा का अस्थायी पद ज्त. केंद्रीय विद्यालय में के प्रारंभिक वेतन पर संगठन।

2

3. नियुक्त व्यक्ति की सेवाएं एक महीने के नोटिस से समाप्त की जा सकती हैं। दोनों तरफ से बिना कोई कारण

बताए तथापि, नियुक्ति प्राधिकारी को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित है नोटिस की निर्धारित अवधि की समाप्ति से पहले सेवाएं नियुक्त व्यक्ति को वेतन और भत्तों के बराबर राशि का भुगतान सूचना की अवधि या अप्रचलित भाग के लिए वहाँ से।

4. यदि वह निर्धारित नियमों और शर्तों पर प्रस्ताव स्वीकार करता है, वह कृपया अपनी स्वीकृति हस्ताक्षरित व्यक्ति को भेज सकता है।

7. संलग्न प्रपत्र में इस पत्र की प्राप्ति के दिनों और रिपोर्ट करें उपर्युक्त केंद्रीय के प्राचार्य के प्रति कर्तव्य के लिए विद्यालय..

सहायक आयुक्त, केंद्रीय विद्यालय संगठन, बॉम्बे क्षेत्र द्वारा दिनांक 21.3.1975 को उत्तरदाता की सेवाओं को दिनांक 30.4.1975 से समाप्त करने के लिए से एक आदेश निकाला गया और उक्त आदेश निम्नानुसार है:

"श्री अरुणकुमार माधवराव सिद्धाये, पी. एच. टी., के. वी., देहू रोड सूचित किया कि संगठन को अब उनकी सेवाओं की आवश्यकता नहीं है 30.4.75 (ए. एन.) से प्रभावी। इसलिए उनकी सेवाएँ उक्त दिनांक से नियमों और शर्तों के अनुसार जो उनकी नियुक्ति के प्रस्ताव में उल्लिखित समाप्त होंगी नियुक्ति पत्र दिनांक 25.6.74 श्री

सिद्धाये को जारी किया गया और वही विधिवत उन्होंने अपने दिनांकित 1.7.74 पत्र के माध्यम से स्वीकार किया। इसे एक महीने का नोटिस समझा जावे।”

एसडी/-

(मदन गोपाल)

सहायक आयुक्त

5. स्थापित वाद में प्रत्यर्थी द्वारा लिया गया प्रमुख आधार उनके द्वारा यह कहा गया था कि उनकी पीठ के पीछे एक जांच की गई थी जिसमें उनके खिलाफ एक निष्कर्ष दर्ज किया गया था और उक्त जांच के आधार पर उनकी सेवाओं को समाप्त कर दिया गया था और इस प्रकार यह सेवाओं को समाप्त करने का एक साधारण आदेश नहीं था, बल्कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पूर्ण उल्लंघन करते हुए सजा के रूप में पारित किया गया था। इसलिए इस संबंध में प्रासंगिक तथ्यों का उल्लेख करना आवश्यक है। एक कैप्टन। वी. के. बालासुब्रमण्यम स्टेशन कमांडर, देहू रोड को 21.2.1975 पर एक पत्र भेजा जिसमें कहा गया था कि उनके बेटे मास्टर वी. के. श्रीनिवासलू, जो नौवीं कक्षा में पढ़ रहे थे, को 18 फरवरी, 1975 को सीने में गंभीर दर्द हुआ था और यह सूचित करने के बावजूद कि वह ठीक नहीं थे, पीटी शिक्षक ने उन्हें छह चक्कर लगाने के लिए मजबूर

किया (लगभग) 4 कि. मी.) विद्यालय के आसपास। चूंकि बच्चा ठीक नहीं था, इसलिए 20 फरवरी को सैन्य अस्पताल में उसकी जांच की गई और डॉक्टर ने उसे कुछ दवाएं लिखवा दीं। दवाएँ दीं और लिखित सलाह दी कि उन्हें एक सप्ताह तक पी. टी. या अन्य व्यायाम नहीं करना चाहिए। यह कक्षा शिक्षक को दिखाया गया था जिसने पी. टी. शिक्षक को लिखित में एक नोट दिया था जिसमें बच्चे को पी. टी. और अन्य अभ्यासों से छूट दी गई थी। डॉक्टर की सलाह और कक्षा शिक्षक के लिखित नोट के बावजूद, पीटी शिक्षक ने लड़के को पीटी करने के लिए मजबूर किया और ऐसा करने में असमर्थ होने के कारण उसे पीटा गया। पत्र में आगे यह उल्लेख किया गया कि यह एकमात्र अवसर नहीं था जब प्रत्यर्थी द्वारा छात्रों को शारीरिक दंड दिया गया था क्योंकि पहले भी इस तथ्य को लेफ्टिनेंट कर्नल जी. वी. लुकास द्वारा स्कूल की कार्यकारी समिति के ध्यान में लाया गया था और प्राचार्य ने इस प्रथा को रोकने का वादा किया था क्योंकि शारीरिक दंड संविधान के नियमों के खिलाफ था।

केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य ने कैप्टन की शिकायत को अग्रेषित कर दिया। बालासुब्रमण्यम केंद्रीय विद्यालय संगठन, बॉम्बे के क्षेत्रीय कार्यालय को 25.2.1975 पर। सहायक आयुक्त, केंद्रीय विद्यालय संगठन ने तब प्रत्यर्थी द्वारा छात्रों को पीटने की शिकायत के संबंध में मूल बयानों के साथ एक रिपोर्ट भेजने के लिए 1.3.1975 पर प्राचार्य को लिखा। रिपोर्ट भेजने के

उद्देश्य से एक जांच की गई थी जिसमें मास्टर वी. के. श्रीनिवासलू सहित आठ छात्रों के बयान दर्ज किए गए थे। प्रधानाचार्य ने पहले प्रत्यर्थी से उनके दिनांकित 26.2.1975 पत्र के माध्यम से स्पष्टीकरण मांगा था जो उन्होंने दिया था। उत्तरदाता की उपस्थिति में छात्रों का बयान दर्ज किया गया जिसमें वे थे, उन्हें सवाल पूछने के लिए प्रेरित किया। उन्हें फिर से अपना केंद्रीय विद्यालय संगठन 1 देने के लिए कहा गया। बयान, जिसे उन्होंने देने से इनकार कर दिया। जांच अधिकारी ने तब अपना बयान प्रस्तुत किया 7.3.1975 और उसी पर राय नीचे पुनः प्रस्तुत की जा रही है:

पूछताछ अधिकारी की राय

“ऊपर दिए गए साक्ष्य के आधार पर, मेरी राय है कि श्री शिंदे, पी. टी. शिक्षक, सेंट्रल स्कूल, देहू रोड मास्टर वी.के. श्रीनिवासलू, नौवीं कक्षा के छात्र को शारीरिक दंड। 18 पर 75 फरवरी। मुझे आगे लगता है कि वह इस अभ्यास में लिस रहा है समय-समय पर छात्रों को शारीरिक दंड देना गंभीरता की अलग-अलग डिग्री।

में श्री शिंदे के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की सिफारिश करता हूं।”

पूछताछ अधिकारी

सहायक आयुक्त, केंद्रीय विद्यालय संगठन, बॉम्बे क्षेत्र इसके बाद 21.3.1975 पर विवादित आदेश पारित किया गया जिसके द्वारा प्रतिवादी को सूचित किया गया कि उसकी सेवाओं की अब आवश्यकता नहीं है और यह 30.4.1975 से समाप्त हो जाएगी।

6. उच्च न्यायालय द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष जिनके आधार पर नीचे दिए गए दो न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों और फरमानों को दरकिनार कर दिया गया था और प्रत्यर्थी द्वारा दायर दूसरी अपील को अपने मुकदमे का आदेश देते हुए अनुमति दी गई थी, जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। पैरा 9 में उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है:

"9 इसके अलावा मामले द्वारा ही यह संकेत दिया गया है कि सेवा की समाप्ति का आदेश जांच शुरू होने के बाद था अपीलार्थी पर आरोप और आरोप के कौन से लेख लगाए गए थे और कुछ गवाहों से पूछताछ की गई। यह स्पष्ट रूप से बताता है कि जानकारी कि उक्त जांच या तो नहीं लाई गई थी या पूरी नहीं की गई थी। अपीलार्थी को उसके समक्ष रखने के उद्देश्य से रखा गया होगा उन परिस्थितियों में

अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का अवसर अन्यथा ऐसा कोई आदेश नहीं होता जो अपीलार्थी को सूचित किया गया कि उक्त जाँच को हटा दिया गया है। कोई नहीं। यह दर्शाने वाला निष्कर्ष कि सेवा की समाप्ति का आदेश अपीलार्थी का कुछ भी नहीं बल्कि उक्त जाँच का परिणाम था जो था न तो कानूनी रूप से पूरा किया गया और न ही हटा दिया गया।”

पुनः पैरा 11 में उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

“11. वर्तमान मामले में नीचे दिए गए दोनों न्यायालयों ने सकल कार्य किए हैं। इस बात की अनदेखी करनेमें कानून की त्रुटि कि सेवा की समाप्ति का उक्त आदेश अपीलार्थी ने उक्त जाँच का पालन किया और न ही कानूनी रूप से पूरी की न ही गिरा। यदि यह मामला होता कि उक्त जाँच को हटा दिया जाता तब यह कहने का कुछ अर्थ होना चाहिए था कि सेवा की समाप्ति के उक्त आदेश में कोई कलंक नहीं था। लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं है। उस जाँच को पूरा किए बिना, अपीलार्थी की सेवा समाप्त कर दी गई है और अपीलार्थी को दंड के दायरे में रखा गया है। भविष्य की अनिश्चितता।”

7. अपीलार्थी केंद्रीय विद्यालय संगठन के विद्वान वकील प्रस्तुत किया है कि प्रतिवादी के खिलाफ की गई जांच एक नहीं थी नियुक्ति आदेश क्योंकि वह विशुद्ध रूप से एक अस्थायी कर्मचारी था और उसकी सेवाओं को बिना कोई कारण बताए दोनों तरफ से एक महीने के नोटिस द्वारा समाप्त किया जा सकता था। अपीलार्थी के विद्वान वकील ने आगे प्रस्तुत किया है कि उच्च न्यायालय ने प्रारंभिक या तथ्य खोजने वाली जांच को नियमित अनुशासनात्मक जांच के साथ तुलना करने और इस निष्कर्ष पर पहुंचने में घोर गलती की है कि प्रतिवादी की सेवाओं को सजा के रूप में समाप्त कर दिया गया था। यह भी आग्रह किया गया है कि समाप्ति आदेश नियुक्ति आदेश के संदर्भ में पारित एक सरल आदेश है और यह गैर-कलंकित है और प्रतिवादी को किसी भी बुरे परिणाम के साथ नहीं जाता है और ऐसी परिस्थितियों में उच्च न्यायालय न्यायालय ने नीचे दिए गए दोनों न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों और फरमानों को दरकिनार करने और प्रत्यर्थी द्वारा दायर मुकदमे का आदेश देने में स्पष्ट रूप से गलती की। दूसरी ओर, प्रत्यर्थी के विद्वान वकील ने कैप्टन द्वारा की गई शिकायत के आधार पर प्रस्तुत किया है। वी. के. बालासुब्रमण्यम ने अपने बेटे की पिटाई के संबंध में एक जांच की थी जिसमें छात्रों के बयान दर्ज किए गए थे और इन परिस्थितियों में प्रतिवादी की सेवाओं को समाप्त करने का आदेश उक्त जांच के परिणाम पर आधारित था और सजा के रूप में पारित किया गया था। यह आग्रह किया गया है कि चूंकि प्रतिवादी को अपना

बचाव करने का कोई अवसर नहीं दिया गया था, इसलिए प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पूरी तरह से उल्लंघन किया गया था और चूंकि आदेश सजा के रूप में पारित किया गया था, इसलिए यह पूरी तरह से अवैध था और इसलिए उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी द्वारा दायर मुकदमे को सही ठहराया।

8. हमने प्रस्तुतियों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है पक्षों के लिए विद्वान वकील और रिकॉर्ड पर सामग्री की भी जांच की है। शुरुआत में यह उल्लेख किया जा सकता है कि प्रतिवादी को पी. टी. के रूप में नियुक्त किया गया था। केंद्रीय विद्यालय संगठन में शिक्षक और इस तरह वह संविधान के अनुच्छेद 311 के अर्थ के भीतर एक नागरिक पद पर नहीं है और उक्त प्रावधान उस पर लागू नहीं होता है। दिनांक 25.6.1974 के नियुक्ति आदेश (नियुक्ति की पेशकश) की शर्तों में से एक यह थी कि उनकी सेवाओं को बिना कोई कारण बताए दोनों तरफ से एक महीने के नोटिस द्वारा समाप्त किया जा सकता था। प्रत्यर्थी ने नियुक्ति आदेश को स्वीकार कर लिया और कर्तव्य में शामिल हो गया और इस तरह नियुक्ति की शर्तों को स्वीकार कर लिया, अर्थात्, उनकी सेवाओं को बिना किसी कारण बताए एक महीने के नोटिस द्वारा समाप्त किया जा सकता था। नियुक्ति आदेश के संदर्भ में उनकी सेवाओं को 21.3.1975 के नोटिस के माध्यम से 30.4.1975 से समाप्त कर दिया गया था। प्रत्यर्थी की सेवाओं को समाप्त करने का आदेश पूरी तरह से हानिरहित आदेश है और इसमें उसके खिलाफ

कोई कलंक नहीं है। यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि सेवाओं की समाप्ति की सूचना प्रत्यर्थी को तब दी गई थी जब उसने 9 महीने से भी कम समय में सेवा करते हैं।

9. विचार के लिए जो प्रश्न उत्पन्न होता है, वह यह है कि क्या प्रत्यर्थी की सेवाओं की समाप्ति के माध्यम से पारित किया गया था दंड या यह नियुक्ति आदेश में उल्लिखित शर्तों के अनुसार पारित किया गया था जिसके द्वारा प्रतिवादी को शारीरिक शिक्षा शिक्षक के अस्थायी पद पर नियुक्त किया गया था। यदि यह पाया जाता है कि समाप्ति एक अन्य प्रश्न उत्पन्न हो सकता है कि क्या समाप्ति आदेश पारित करने से पहले एक औपचारिक विभागीय जांच की गई थी और क्या प्रतिवादी को उक्त जांच में अपना बचाव करने का पर्याप्त अवसर दिया गया था। यह देखा जाएगा कि कैप्टन द्वारा की गई शिकायत। बी. के. बालासुब्रमण्यम अपने बेटे मास्टर वी. के. श्रीनिवासलू को ऐसा करने के लिए मजबूर करने के बारे में जब वह सीने में दर्द कर रहा था और अस्वस्थ था और डॉक्टर की सलाह के बावजूद उसे पीटी और अन्य व्यायाम करने के लिए मजबूर कर रहा था और उसे पीटने के लिए भी प्राचार्य द्वारा केंद्रीय विद्यालय संगठन, बॉम्बे के क्षेत्रीय कार्यालय को छह चक्कर (4 किलोमीटर) लगाए गए थे। केंद्रीय विद्यालय संगठन के सहायक आयुक्त ने प्राचार्य को उन छात्रों के मूल बयानों के साथ एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा, जिन्हें प्रतिवादी द्वारा पीटा

गया था। प्राचार्य मास्टर वी. के. श्रीनिवासलू से संबंधित घटना और प्रत्यर्थी द्वारा अन्य छात्रों को दी गई शारीरिक सजा के चश्मदीद गवाह नहीं थे। इसलिए, पूर्ण तथ्यों का पता लगाने के लिए संबंधित छात्रों से पूछताछ करना आवश्यक था। यदि इस पूछताछ के दौरान प्रत्यर्थी को भाग लेने की अनुमति दी गई थी और कुछ प्रश्न छात्रों के लिए, इसका मतलब यह नहीं होगा कि इस तरह से की गई जांच ने एक औपचारिक विभागीय जांच का रूप ले लिया। प्रत्यर्थी पर कोई आरोप नहीं लगाया गया था और न ही छात्रों को शपथ लेने के लिए कहा गया था।

उच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी करते हुए अभिलेख पर साक्ष्य को गलत पढ़ा है कि प्रत्यर्थी को आरोपों के लेख दिए गए थे। जाँच का सीमित उद्देश्य प्रासंगिक तथ्यों का पता लगाना था ताकि केंद्रीय विद्यालय संगठन को एक सही रिपोर्ट भेजी जा सके। की गई जाँच के तहत नहीं हो सकता है नियुक्ति आदेश जो स्पष्ट रूप से नियुक्ति प्राधिकारी को कोई कारण बताए बिना एक महीने के नोटिस द्वारा प्रत्यर्थी की सेवाओं को समाप्त करने की शक्ति प्रदान करता है। इसलिए, प्रतिवादी की सेवाओं को सजा के रूप में समाप्त नहीं किया गया था।

10. इसी तरह के एक प्रश्न पर महाराष्ट्र राज्य बनाम में काफी विस्तार से विचार किया गया था। वीरप्पा आर. साबोजी, ए. आई. आर. (1980) एस. सी. 42, और यह निम्नानुसार देखा गया: -

“आम तौर पर इस न्यायालय द्वारा अधिकांश मामलों में निर्धारित नियम यह है कि आपको आदेश को देखना होगा और यह पता लगाना होगा कि क्या यह सरकारी कर्मचारी पर कोई कलंक लगाता है। ऐसे मामले में यह कोई धारणा नहीं है कि आदेश मनमाना या दुर्भावनापूर्ण है जब तक कि सरकार द्वारा एक बहुत मजबूत मामला नहीं बनाया जाता है और साबित नहीं किया जाता है। नौकर जो इस तरह के आदेश को चुनौती देता है।”

उत्तर प्रदेश और अन्न राज्य में बनाम कौशल किशोर शुक्ला, (1991) एस. सी. सी. 691, कर्मचारी को सहायक के रूप में 18.2.1977 पर तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया था। लेखा परीक्षक और उनकी नौकरी को कई मौकों पर बढ़ाया गया था और अंतिम विस्तार 21.1.1980 पर दिया गया था, जो 28.2.1981 पर समाप्त होने वाला था। उनकी सेवाओं को 23.9.1980 पर समाप्त कर दिया गया था। बर्खास्तगी आदेश को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि उनके खिलाफ कदाचार के कुछ आरोप लगाए गए थे, जिसके बारे में एक एकतरफा जांच की गई थी जिसमें उन्हें सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया था। उच्च न्यायालय ने कर्मचारी की इस दलील को स्वीकार कर लिया कि सेवाओं को समाप्त करने का आदेश कदाचार के आरोपों और पूर्व-पक्षीय जांच रिपोर्ट पर आधारित था और

तदनुसार समाप्ति आदेश। इस न्यायालय ने केंद्रीय विद्यालय संगठन 1 के साथ उच्च न्यायालय के फैसले को दरकिनार कर दिया: निम्नलिखित टिप्पणियाँ:

“प्रतिवादी के पास एक अस्थायी सरकारी कर्मचारी होने के नाते कोई नहीं था पद धारण करने का अधिकार, और सक्षम प्राधिकारी ने उसे समाप्त कर दिया प्रत्यर्थी की उपयुक्तता का पता लगाने के लिए प्रारंभिक प्रकृति का था और सेवा में निरंतरता। दंडात्मक कार्यवाही का कोई तत्व नहीं था क्योंकि कोई आरोप तय नहीं किया गया था, कोई जांच अधिकारी नियुक्त नहीं किया गया था, नहीं निष्कर्षों को दर्ज किया गया, इसके बजाय एक प्रारंभिक जांच की गई और प्रारंभिक जांच की रिपोर्ट सक्षम प्राधिकारी ने समाप्त कर दी के अनुसार एक हानिरहित आदेश द्वारा प्रतिवादी की सेवाएं उनकी सेवा के नियम और शर्तों। केवल यह तथ्य कि इससे पहले समाप्ति का आदेश जारी करना, प्रत्यर्थी के खिलाफ एक जांच लड़कों के कोष के अनधिकृत लेखा परीक्षा के आरोपों के संबंध में था धारित, समाप्ति के क्रम की प्रकृति को उस में नहीं बदलता प्रतिवाद में निहित-पक्ष की ओर से दायर बचाव के माध्यम से शपथ पत्र

अपीलार्थियों की प्रकृति और चरित्र भी नहीं बदलते हैं
समाप्ति का आदेश।”

एस. पी. वासुदेव बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, ए. आई. आर. (1975) एस. सी. 2292 में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि जहां किसी ऐसे व्यक्ति को प्रत्यावर्तित करने का आदेश, जिसे पद का कोई अधिकार नहीं था, प्रत्यक्ष रूप से यह नहीं दर्शाता है कि उसे दंड के रूप में प्रत्यावर्तित किया जा रहा था या उस पर कोई कलंक नहीं लगाया जाता है, अदालतें आम तौर पर उस आदेश के पीछे यह देखने के लिए नहीं जाएंगी कि क्या उस आदेश के पीछे कोई प्रेरक कारक थे। ये दोनों निर्णय तीन विद्वान न्यायाधीशों की पीठों द्वारा दिए गए हैं।

11. रवींद्र कुमार मिश्रा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम लिमिटेड, और अन्य आई. आर. (1987) एस. सी. 2408, अपीलार्थी को 30.10.1976 पर नियुक्त किया गया था और उसे अस्थायी स्थिति में काम करते हुए दो पदोन्नति मिली थी और 1982 वे उप-उत्पादन प्रबंधक के रूप में काम कर रहे थे। आई. डी.1 पर उन्हें निलंबित कर दिया गया और निलंबन आदेश में कहा गया कि केंद्रीय प्रबंधक द्वारा की गई प्रारंभिक पूछताछ के परिणामस्वरूप यह पता चला था कि अपीलार्थी कदाचार, कर्तव्य की अवहेलना, कुप्रबंधन और टेरिकॉट कपड़े का काल्पनिक उत्पादन दिखाना। पर निलंबन आदेश को रद्द कर दिया गया था और उसके बाद

आई. डी.1 पर उनकी सेवाओं को समाप्त करने का एक साधारण आदेश पारित किया गया था जिसमें कहा गया था कि उनकी सेवाओं की अब आवश्यकता नहीं है और नोटिस प्राप्त होने की तारीख से उनकी सेवाओं को समाप्त माना जाएगा। इसमें आगे यह उल्लेख किया गया था कि वह नोटिस अवधि के बदले में एक महीने का वेतन प्राप्त करने का हकदार होगा। समाप्ति आदेश को अपीलार्थी द्वारा इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि यह दंडात्मक प्रकृति का था, जो इस तथ्य से भी प्रदर्शित किया गया था कि बर्खास्तगी के आदेश से कुछ समय पहले एक निलंबन आदेश पारित किया गया था जिसमें उनके खिलाफ कदाचार के एक विशिष्ट आरोप का उल्लेख किया गया था। पहले के कई फैसलों का उल्लेख करने के बाद इस न्यायालय ने रिपोर्ट के पैराग्राफ 6 के तहत कर्मचारी द्वारा की गई चुनौती को खारिज कर दिया: -

"6..... इस न्यायालय की कई आधिकारिक घोषणाओं में, समाप्ति के आदेश के प्रभाव का पता लगाने के लिए उद्देश्य और आधार की अवधारणा को लाया गया है। यदि अस्थायी सेवा में अधिकारी के अपराध को संचालन उद्देश्य के रूप में लिया जाता है सेवा को समाप्त करने के आदेश को दंडात्मक नहीं माना जाता है, जबकि यदि समाप्ति का आदेश उस पर आधारित है, तो समाप्ति को दंडात्मक कार्रवाई माना जाता

है। यह इस तथ्य के कारण है कि प्रत्येक नियोक्ता के लिए अस्थायी पदधारी की सेवा का आकलन करना आवश्यक है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या उसकी नियुक्ति में उसकी पुष्टि की जानी चाहिए या उसकी सेवाओं को समाप्त किया जाना चाहिए। यह पता लगाना भी आवश्यक हो सकता है कि अधिकारी पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए या नहीं। अस्थायी आधार पर कुछ और समय के लिए। चूंकि एक अस्थायी कर्मचारी या एक उच्च पद पर एक कार्यवाहक कर्मचारी दोनों के संबंध में इस तरह का मूल्यांकन केवल इसलिए आवश्यक होगा क्योंकि उपयुक्त प्राधिकारी एक मूल्यांकन करने के लिए आगे बढ़ता है और अपने विचारों का रिकॉर्ड छोड़ देता है, इसलिए इस तरह के मूल्यांकन के बाद समाप्ति का आदेश देने के लिए इसका उपयोग करने के लिए उपलब्ध नहीं होगा, जो दंडात्मक होगा।”

12. पवनेंद्र नारायण वर्मा बनाम संजय गांधी पीजीआई ऑफ मेडिकल विज्ञान और अन्य (2002) एस. सी. सी. 520, पहले के निर्णयों की बड़ी संख्या का उल्लेख करने के बाद, इस मुद्दे पर कानून को बहुत स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया गया है निम्नलिखित तरीके से:

"न्यायिक रूप से विकसित परीक्षणों में से एक यह निर्धारित करने के लिए है कि क्या वास्तव में समाप्ति का आदेश दंडात्मक है, यह देखना है कि क्या समाप्ति से पहले (ए) नैतिक अधमता कदाचार से जुड़े आरोपों की पूर्ण पैमाने पर औपचारिक जांच (बी) थी जो (सी) अपराध की खोज में समाप्त हुआ। यदि तीनों कारक मौजूद हैं समाप्ति को दंडात्मक माना गया है चाहे वह किसी भी रूप में हो समाप्ति आदेश। इसके विपरीत यदि तीन कारकों में से कोई एक है गायब है, समाप्ति को बरकरार रखा गया है। आम तौर पर जब परिवीक्षाधीन की नियुक्ति समाप्त हो जाती है इसका मतलब है कि परिवीक्षाधीन नौकरी के लिए अयोग्य है, चाहे वह दुराचार या अयोग्यता के कारण हो, समाप्ति आदेश में उपयोग की जाने वाली भाषा जो भी हो। हालांकि कड़ाई से बोलते हुए, कलंक समाप्ति में निहित है, एक साधारण समाप्ति कलंकित नहीं है। एक समाप्ति आदेश जो स्पष्ट रूप से बताता है कि प्रत्येक क्रम में क्या निहित है। परिवीक्षाधीन की नियुक्ति की समाप्ति भी कलंकित नहीं है। एक कलंक के रूप में गणना करने के लिए, आदेश एक ऐसी भाषा में होना चाहिए जो नौकरी के लिए केवल अनुपयुक्तता के अलावा कुछ का आरोप लगाती है।"

13. पंजाब राज्य में अ. सुखविंदर सिंह, (2005) 5 एस. सी. सी. 569, एक पीठ ने पाया कि, इस न्यायालय के 1 पहले के फैसलों का उल्लेख करने के बाद, जिनमें ऊपर उल्लिखित फैसले भी शामिल हैं, ने यह फैसला सुनाया। रिपोर्ट के पैरा 19 के तहत सिद्धांतः

“यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि कोई भी कर्मचारी चाहे वह परिवीक्षाधीन हो या अस्थायी रूप से बिना किसी तुकबंदी या कारण के मनमाने ढंग से छुट्टी दी जाएगी या वापस कर दी जाएगी। जहां एक वरिष्ठ अधिकारी, खुद को संतुष्ट करने के लिए कि संबंधित कर्मचारी को सेवा में बने रहना चाहिए या नहीं, इस उद्देश्य के लिए पूछताछ करता है तो यह मानना गलत होगा कि जो जांच की गई थी, वह वास्तव में सजा देने के उद्देश्य से की गई थी। यदि प्रत्येक मामले में जहां किसी प्रकार की तथ्य खोजने वाली जांच की जाती है, जिसमें कर्मचारी को या तो स्पष्टीकरण देने का अवसर दिया जाता है या जांच उसकी पीठ के पीछे रखी जाती है, तो यह माना जाता है कि छुट्टी या सेवा से बर्खास्तगी का आदेश दंडात्मक प्रकृति का है, यहां तक कि यह तय करने के लिए वरिष्ठ अधिकारी द्वारा एक प्रामाणिक प्रयास है कि क्या संबंधित कर्मचारी को सेवा में बनाए रखा

जाना चाहिए या दंड के आदेश के रूप में बताए जाने का जोखिम नहीं होना चाहिए। परिवीक्षा या आदेश की अवधि के दौरान परिवीक्षाधीन को छुट्टी देने का निर्णय एक अस्थायी कर्मचारी की सेवा को समाप्त करने के लिए विभिन्न विभागों के नियुक्ति प्राधिकरण या प्रशासनिक प्रमुखों द्वारा लिया जाता है जो न्यायिक रूप से प्रशिक्षित लोग नहीं हैं। के वरिष्ठ अधिकारी विभागों को एक कर्मचारी से काम लेना पड़ता है और वे यह तय करने के लिए सबसे अच्छे लोग हैं कि क्या एक कर्मचारी को सेवा और एक स्थायी कर्मचारी बनाया या उसके प्रदर्शन आचरण और नौकरी के लिए समग्र उपयुक्तता को ध्यान में नहीं रखते हुए। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है कि एक परिवीक्षाधीन परीक्षण पर होता है और एक अस्थायी कर्मचारी को इस पद का कोई अधिकार नहीं होता है। यदि केवल प्रासंगिक का पता लगाने के लिए एक जांच आयोजित करना है वस्तुनिष्ठ विचारों पर निर्णय लेने के लिए तथ्यों को माना जाता है कि कर्मचारी को सेवा में जारी रखना है या उसे स्थायी बनाना है। दंड अधिरोपित करने के उद्देश्य से जांच और "दंडात्मक चरित्र" के परिणामस्वरूप सेवा के निर्वहन या समाप्ति के आदेश के रूप में परिवीक्षाधीन या

परिवीक्षाधीन के बीच मौलिक अंतर अस्थायी कर्मचारी और एक स्थायी कर्मचारी पूरी तरह से होगा मिटा दिया गया जो पूरी तरह से गलत होगा।”

14. जैसा कि ऊपर दिखाया गया है, उनके खिलाफ की गई जांच की प्रकृति प्रतिवादी केवल एक प्रारंभिक या तथ्य खोजने वाली जांच थी और प्रतिवादी के खिलाफ कोई औपचारिक पूर्ण विभागीय जांच नहीं की गई थी। वास्तव में, जांच अधिकारी ने स्वयं सिफारिश की थी कि प्रतिवादी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। हालांकि, अधिकारियों ने प्रतिवादी के खिलाफ अनुशासनात्मक जांच नहीं करने का फैसला किया और उसे किसी भी आरोप के साथ पेश नहीं किया या उस संबंध में कोई और कदम नहीं उठाया। इसके बजाय उन्होंने नियुक्ति आदेश के नियमों और शर्तों के तहत शक्ति का प्रयोग करने का विकल्प चुना। समाप्ति आदेश पूरी तरह से हानिरहित है और इसमें कोई कलंक नहीं है प्रत्यर्थी पर और न ही यह किसी भी बुरे परिणाम के साथ उसका दौरा करता है। ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय ने पूरी तरह से गलत आधार पर कार्रवाई की है और जांच को माना है जो केवल एक नियमित मामले में प्रारंभिक या तथ्य खोजने वाली जांच थी। अनुशासनात्मक जाँच, जो यहाँ मामला नहीं था। इन परिस्थितियों में उच्च न्यायालय का निर्णय कानूनी रूप से पूरी तरह से गलत है और इसे दरकिनार किया जाना चाहिए।

15. प्रतिवादी के विद्वान वकील ने समशेर सिंह पर भरोसा किया है वी. पंजाब और अन्न राज्य (1974) 2 एस. सी. सी. 831, बिशन लाल गुप्ता बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (1978) 1 एस. सी. सी. 202, अनूप जैसवाल बनाम भारत सरकार और एएनआर (1984) 2 एस. सी. सी. 369 और दीप्ति प्रकाश बनर्जी बनाम सत्येंद्र नाथ बोस राष्ट्रीय बुनियादी विज्ञान केंद्र, कलकत्ता और अन्य (1999) 3 एस. सी. सी. 60 ने उनकी इस दलील के समर्थन में कि सेवाओं को समाप्त करने का विवादित आदेश सजा के रूप में पारित किया गया था और जैसा कि यह खुद का बचाव करने का अवसर दिए बिना किया गया था, समाप्ति आदेश अवैध था। बिशन लाल गुप्ता (ऊपर) में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि एक परिवीक्षाधीन के खिलाफ जांच के पीछे का इरादा दंडित करने के लिए एक पूर्ण विभागीय परीक्षण आयोजित करना नहीं था, बल्कि परिवीक्षाधीन की सेवा में बने रहने के लिए केवल उपयुक्तता निर्धारित करने के लिए एक संक्षिप्त जांच थी और परिवीक्षाधीन को पर्याप्त अवसर दिया गया था। कारण दर्शाओ नोटिस में उसके खिलाफ जो भी आरोप लगाया गया था, उसका लिखित में जवाब देने के लिए, ऐसी संक्षिप्त जांच के बाद समाप्ति का हानिरहित आदेश नहीं हो सका दंड का आदेश कहा जाए जो उसे संविधान के अनुच्छेद 311 द्वारा अनुध्यात पूर्ण जांच का अधिकार देता है। अनूप जयसवाल (ऊपर) और दीप्ति प्रकाश बनर्जी (ऊपर) में यह तथ्य पाया गया कि कथित कदाचार सेवाओं को समाप्त करने के विवादित आदेश का आधार था। पहले के सभी

निर्णयों के विश्लेषण के बाद पवनेंद्र नारायण वर्मा बनाम में कानून का सिद्धांत निर्धारित किया गया है। ऊपर उल्लिखित चिकित्सा विज्ञान के संजय गांधी पीजीआई। इसलिए, प्रत्यर्थी के विद्वान वकील द्वारा उद्धृत अधिकारी किसी भी तरह से उसके मामले को आगे नहीं बढ़ाते हैं।

16. परिणामस्वरूप, अपील की अनुमति दी जाती है और निर्णय और डिक्री दी जाती है। 1988 की दूसरी अपील छव.463 में पारित दिनांक 5.3.2002 और उच्च न्यायालय द्वारा समीक्षा याचिका में पारित 3.11.2003 के आदेश को भी दरकिनार कर दिया गया है। द्वारा दायर मुकदमे को खारिज करते हुए नीचे दिए गए दो न्यायालयों द्वारा पारित आदेश उत्तरदाता की पुष्टि की जाती है। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं।

वीएस

अपीलों की अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी रीतिका श्रोती (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।